

एक दृष्टि उत्तराखण्ड की A View of Uttarakhand

Paper id: 15544 Submission: 11/01/2022, Date of Acceptance: 21/01/2022, Date of Publication: 23/01/2022

सारांश

कृषि उद्योग और पर्यटन उत्तराखण्ड राज्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनकी वजह से ही राज्य में अर्थव्यवस्था बढ़ती है। केदारनाथ आपदा और कोविड-19 महामारी में राज्य का पर्यटन और अन्य व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुए। उत्तराखण्ड अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर वन पंचायतों का गठन किया गया। प्रत्येक वन पंचायत कार्य करवाने के लिए अपने नियम बनाती है। पहले राज्य में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी पर अब पूरी छूट है। 20 वर्षों में इस पर्वतीय राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 14 गुना बढ़ा हो चुका है। 9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य अपने रूप में आया। उस समय राज्य का बजट केवल 924 करोड़ रुपये था। अब इसमें लगभग 55 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कृषि एक विकसित होता उद्यम है जो राज्य के लोगों के लिए जीने के लिए मुख्य है।

Agriculture industry and tourism hold their special place in the state of Uttarakhand. It is because of them that the economy grows in the state. The state's tourism and other business were badly affected by the Kedarnath disaster and the Covid-19 pandemic. Uttarakhand is the only state where forest panchayats were constituted. Each Van Panchayat makes its own rules for getting the work done. Earlier it was not allowed to buy land in the state but now there is complete exemption. The size of the economy of this hill state has grown 14 times in 20 years. The state of Uttarakhand came into its own form on 9 November 2000. At that time the budget of the state was only 924 crores. Now it has increased by about 55 times. Uttarakhand is an agricultural state. Agriculture is a growing enterprise in the state which is the main source of livelihood for the people of the state.



रश्मि गोयल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं
अध्यक्षा,
भूगोल विभाग,
शम्भुदयाल पी0जी0
कॉलेज,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश भारत



मुख्य शब्द: कृषि, उद्योग, पर्यटन, आपदा

Keywords: Agriculture, Industry, Tourism, Disaster

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में गरीब किसानों के पास पर्याप्त भूमि न होने के कारण वो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर नौकरी की खोज में निकल जाते हैं। सरकार ने भी कोई ढांचा तैयार नहीं किया है। एक सन्त कश्मीर के शेख नुरुद्दीन अहमद (नुन्द ऋषि) हुए हैं जिन्होंने कहा था कि -” अन्न पोशों तले, येली पोशी बन”

अर्थात जब तक वन रहेंगे, भरपूर अन्न रहेगा। 19 वीं और 20 वीं शताब्दी में वन संरक्षण हेतु सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये गये किन्तु उसमें गाँव की जनता के विचारों को तथा भागीदारी को अधिक महत्व न मिलने के कारण सफलता नहीं मिल पायी। वह अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। उस समय में अधिक ज्ञान न होने के कारण भूस्खलन, महामारी तथा अकाल जैसी आपदा को दैवी विपदा मानते थे। महिलाओं का यह नारा सम्पूर्ण विश्व में फैल रहा है।

”क्या है जंगल के उपचार ? मिट्टी, पानी और बयार,

मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

मिट्टी तथा जल प्रमुख पर्यावरणीय उपज है और यही मनुष्य के जीवित रहने का आधार है।

साहित्यावलोकन

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कृषि के लिए मिट्टी, जलवायु, की आवश्यकता पड़ती है। FIBL सर्वे के द्वारा 2008 में कृषि बहुत से देशों में बहुत तेजी से बढ़ी है। स्विट्जरलैण्ड 30.4 मिलियन हेक्टेयर (2006), यूरोप (24%) Latin America (16%) जैविक खेती पिछले- साल की तुलना में 1.8 मिलियन हेक्टेयर बढ़ी है। 2005 वासमती चावल 2002-03 में 16 हेक्टेयर से 2,200 हेक्टेयर-उगा जिसमें 2100 किसान लगे हुए थे। आय और पोषण दानों को बढ़ावा देने के लिए नई या अल्पविकसित फसलों, फलों और सब्जियों और ऊंचे मूल्य वाले पशु उत्पादों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीबी और भोजन तक पहुँच की कमी खाद्य असुरक्षा के मौजूदा मुख्य कारण है। वैश्विक समुदायों के कृषि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। निर्धनों की खाद्य सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बताया है। ये खतरे खाद, बीज, खाद्य उत्पादन में कमी कृषि उत्पादन की कीमतें, कृषि का व्यवसायीकरण आदि स्रोतों से उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 2016-17 में उत्पादित 1.82 मिलियन टन अनाज के उत्पादन को 2025 तक 2.5 मिलियन टन तक बढ़ाना होगा। राज्य के जल संसाधन की मौजूदगी के लिए 2040 तक संसाधन का प्रबंधन आवश्यक है कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए 2019-20 में इसके लिए चार करोड़ रुपये बँटे गये हैं। 2017-18 में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों ने 11%, 49%, 40% का योगदान दिया। 2019-20 में राज्य ने शिक्षा के लिए 12% भाग दिया है। औरों के मुकाबले उत्तराखण्ड का आवंटन ज्यादा है। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए 8% का तथा कृषि के लिए 7.3% भाग आबंटित किया है। ग्रामीण विकास के लिए 6.9% तथा सड़क और पुल के लिए 3.2% तथा पुलिस के लिए 4.2% का आबंटन किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. फसल- विशेष की आवश्यकता एवं भूमि के गुणों के आधार पर उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण करना।
2. कृषकों का तैयारी के साथ मार्गदर्शन करना।
3. सिंचाई में जो जल प्रयोग होता है उसकी जाँच करना
4. प्राकृतिक-सन्तुलन के लिए वृक्षारोपण के कार्यों को गति देना।

अध्ययन क्षेत्र

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है उत्तराखण्ड का नाम पहले उत्तरांचल था 01 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखण्ड कर दिया गया। उत्तराखण्ड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम हिमाचल, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पुरातत्व सबूतों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि पुराने समय से ही उत्तराखण्ड में मानवों का वास रहा है। उत्तराखण्ड नाम का अर्थ उत्तर की भूमि या उत्तर दिशा की तरफ बसी भूमि स्वतन्त्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य 'असम' था उसके बाद जम्मू और कश्मीर दूसरा तथा तीसरा राज्य नागालैण्ड बना। उत्तराखण्ड 10 वाँ हिमालयी राज्य बना।

राज्य का विस्तार

1. Latitude:- 30.0668° N
2. Longitude:- 79.0193° E
3. Area:- 53.483Km²
4. Highest elevation (Nanda Devi)-7816m.(25,643ft)
5. Lowest elevation (sharda sagar Reservoir)190m.(620 ft)
6. Population-11.4 million

भारत के 27 वें राज्य उत्तराखण्ड-9 नवम्बर, 2000 को अपने रूप में आने से पूर्व उत्तर प्रदेश का भाग था। यहाँ पवित्र स्थल तथा मंदिर होने के कारण उत्तराखण्ड को देवों की भूमि कहा जाता है।

विषय विवेचन

उत्तराखण्ड में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के कारण पावर टीलर एक उपयोगी यन्त्र है। जहाँ पर ट्रैक्टर को नहीं ले जाया जा सकता वहाँ पर इस यन्त्र के द्वारा आसानी से जुताई की जा सकती है। उन्नत कृषि यन्त्रों को किसानों को उपलब्ध कराकर खाने पीने के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेजर लैण्ड लेवलर से खेतों को समतल तथा पानी भराव की समस्या को हल किया जा सकता है। उत्तराखण्ड में कई आन्दोलन जैसे चिपकों आन्दोलन जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। उत्तराखण्ड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी0 में 92.57% भाग पहाड़ी और 7.43% भाग मैदानी है। कुल भूमि का 65 %भाग वन विभाग के पास है जिसके वनभूमि कहते हैं। 2008-09 तक 13% क्षेत्र में कृषि होती थी। तब उत्तराखण्ड में 7.7 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती थी। अब यह 2020 वर्ष में घटकर 6.48 लाख हेक्टेयर तक रह गई है। राज्य में 49.85%कृषि क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा है। भौगोलिक संरचना, जलवायु, वनस्पति आदि का अपवाह तन्त्र पर प्रभाव पड़ता है। इसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों को भी शामिल किया जाता है राज्य में अधिकतर नदियों का प्रवाह दक्षिण या दक्षिण-पूर्व दिशा में है। मुख्यतः- काली नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तन्त्र है। राज्य की जलवायु पर पर्वत की दिशा, समुद्र तल से अधिक ऊँचाई, ढाल की तीव्रता, आदि का प्रभाव पड़ता है। गर्मी, सर्दी, वर्षा, ऋतु में भी जलवायु का असर पड़ता है।

राज्य में भूरी मिट्टी कछार की मिट्टी, क्वार्टजाइट मिट्टी, ज्वालामुखीय मिट्टी पायी जाती है। यह मिट्टी हल्की और उपजाऊ होती है। वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि वनस्पतियों के लिए उपयुक्त होती है जो विभिन्न ऊँचाई पर उगती है। पहाड़ों की ढलानें विशाल घास के मैदानों से ढकी रहती हैं जिन्हें उत्तराखण्ड में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखण्ड में कृषि समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती, स्थानान्तरण खेती आदि के द्वारा की जाती है। उत्तराखण्ड में मैग्नेसाइट, टाल्क, खाड़िया चौक, फास्फेट, फास्फोरस, डोलोमाइट, सेलखड़ी गंधक, जिप्सम, लोहा, तॉबा, ग्रेफाइट, सोना, चॉदी यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं।

प्रगति करता उत्तराखण्ड

बाजपेयी सरकार और मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की वजह से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए।

1999-2002 में राज्य में घरेलू उत्पाद में उद्योगों की 19.2% की हिस्सेदारी थी जो बढ़कर 2020 में 48.41% तक आ गयी है। 2021 तक राज्य में 53563 छोटे उद्योग और 290 बड़े उद्योग स्थिर हो गये हैं। इनमें 43 हजार करोड़ से अधिक पूंजी खर्च हुई है। वर्ष 2011-12 में 3530 करोड़ के उत्पादों का निर्यात जो अब 2019-20 में 16971 करोड़ तक हो गया है। उत्तराखण्ड में 23 हजार सरकारी स्कूल है महाविद्यालयों की संख्या 36 से 106 पहुँच गयी है।

उत्तराखण्ड में सड़कों की स्थिति (किलोमीटर में)

राष्ट्रीय राजमार्ग - 2091.34

प्रादेशिक राजमार्ग - 4511.13

मुख्य जिला सड़कें - 2113.18

अन्य जिला सड़कें - 2697.32

ग्रामीण सड़कें - 25388.92

पहले पहाड़ों पर अपनों से बात करना मुश्किल होता था पर अब 2018 में एक लाख तीन हजार लैण्डलाइन, जबकि मोबाइल 13 लाख 59 हजार 534 पर पहुँच गये हैं वर्तमान में तो और भी अच्छा हो गया है। वर्ष 2020-21 में उत्तराखण्ड में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 51,125 वर्ग कि०मी० के कुल क्षेत्र में से लगभग 71.05% भूमि वन आच्छादित है। 13.41% वन क्षेत्र वन पंचायतों के प्रबंधन में आता है। उत्तराखण्ड के सात जिलों में वन आवरण की प्रगति हुई है। जबकि

बागेश्वर - 34

नैनीताल -66

हरिद्वार - 27

रूद्रप्रयाग - 11

ऊधमसिंह नगर - 337

उत्तरकाशी - 35 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल की कमी वन आवरण में हुई है। उत्तराखण्ड घूमने की दृष्टि से बहुत अच्छा राज्य है जहाँ पर लोग मनोरंजन तथा आनन्द प्राप्ति के लिए जाते हैं। वहाँ की वादियों में लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। कोराना महामारी में पर्यटन के कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटकों के द्वारा ही राज्य में अच्छी खासी कमाई हो जाती है नहीं तो खाली रहना पड़ता है। वन कितने महत्वपूर्ण है इस बात का ग्रामीण लोगों को ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। वन उनके जीवन-यापन के लिए आधारभूत स्तम्भ है। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वनों के समाप्त होने से उनका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है।

सुझाव

1. चारधाम ऑल वेदर राडे परियोजना का काम पूर्ण हो चुका है लेकिन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है।
3. बिजली समस्या
4. शिक्षा के स्तर
5. सुविधायें पूरी न होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. पर्यटन
7. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
8. खेतों की पैदावार में वृद्धि कराना
9. व्यावसायिक फसलों के तौर पर फलदार वृक्षों का विकास करना।
10. पर्यटकों के लिए कम और अधिक मूल्य के होटल होने चाहिए
11. विश्राम के लिए जगह-जगह पर वृक्षों का निर्माण होना चाहिए।

12. ग्रामवासियों को गाँवों के समीप ही ईंधन तथा चारा उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड पर्यटक की नजर से काफी खुशहाल राज्य है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटन घूमने आते हैं। उत्तराखण्ड के पास सीमित संसाधन होते हुए भी राज्य ने देश विदेश में अपनी पहचान बनायी है। इस राज्य का पर्यावरण, जल, ऊर्जा, शुद्ध हवा काफी अच्छा है। उत्तराखण्ड राज्य में गंगा, यमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी आदि नदियों के होने से जल की पूर्ति होती है। राज्य में जड़ी बूटियों का भी काम है जिससे बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता है राज्य और भी राज्यों को बिजली प्रदान करता है। उत्तराखण्ड राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी बनाये गये हैं। लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह राज्य देवों की भूमि होने के साथ-साथ प्रकृति की सुन्दरता में अपना स्थान रखता है। हस्तशिल्प कला और हथकरघा प्रमुख उद्योग हैं। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आन्दोलन चलाया गया। चिपको आन्दोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. वृक्षारोपण में उन प्राजातियों के वृक्षों को वरीयता देना जिनकी पर्यावरणीय उपज अधिक हो न कि व्यावसायिक उपज अधिक।
2. कृषि भूमि तथा गाँवों के चारों ओर कवर के रूप में वनों का विकास करना।
3. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी तथा स्थाई कृषि का विकास किया जाए।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय-समय पर शिविरों का आयोजन भी होता रहा है। राष्ट्रीय उद्यान पशु विहार तथा सुरक्षित वनों की दृष्टि से उत्तराखण्ड पूरे देश में सर्वाधिक सम्पन्न है। 30 दिसम्बर 2021 के दैनिक जागरण में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखण्ड में ₹0 17,500/- करोड़ से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बताया है।

लोकार्पण (₹0 3,420 करोड़) शिलान्यास (₹0 14,127 करोड़) प्रकृति प्रेमी आशा करते हैं कि देश और दुनिया, अतीत की तरह भविष्य में भी अपने प्रश्नों के समाधान के लिए उत्तराखण्ड को देखते रहेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. न्यूजपेपर की सहायता से।
2. स्वयं के द्वारा लिखा गया है।
3. Google की सहायता से।
4. *Uttarakhand state perspective and strategic plan, 2009-2027*
5. कृषि भूगोल- आर0सी0 तिवारी, बी0एन0सिंह
6. पर्यावरण भूगोल-डॉ0 विजय कुमार तिवारी